

**शहरी विकास विभाग**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार**  
**9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली**

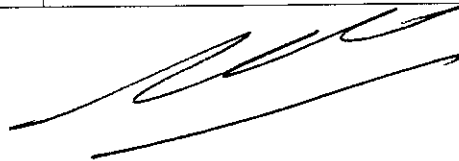
विधायक का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 303

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पिछले तीन माह से दिल्ली में सीलिंग जारी है;	<b>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</b> जी हां । <b>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</b> जी हां । <b>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</b> जी हां ।
ख	यदि हाँ, तो सरकार ने व्यापारियों को इससे राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;	<b>शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)</b> सरकार इस विषय में अंतरिम आवेदन माननीय मॉनटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों पर सिलिंग के विषय में छुट देने के लिए अंतरिम आवेदन फाईल कर चुकी है। <b>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</b> डी.डी.ए. ने मास्टर प्लान में संशोधन करके व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की परन्तु यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
ग	क्या व्यापारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार का इस मामले को को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है;	<b>शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)</b> उपरोक्त 'ख' के अनुसार <b>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</b> इस विषय में डी.डी.ए. एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा एफिडेविट फाईल किये जा चुके हैं।
घ	मननीय उपराज्यपाल से 8 फरवरी को मंजूरी मिलने के बाद भी 351 सड़कों को सीलिंग से राहत देने की फाइल पर अब तक कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;	<b>शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)</b> सरकार इस विषय में अंतरिम आवेदन माननीय मॉनटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों पर सिलिंग के विषय में छुट देने के लिए अंतरिम आवेदन फाईल कर चुकी है। <b>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</b> दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 04.05.2007 को 307 सड़कें एवं दिनांक 07.05.2007 को 44 सड़कें स्टैंडिंग कमेटी से पास कराकर तथा तत्पश्चात निगम से स्वीकृत करवाकर 351 सड़कों (307+44) के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार को भेज दिया था तथा दिल्ली सरकार द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका जबाब भी निगम के द्वारा दिल्ली सरकार को भेज दिया गया था।
ङ	क्या यह सत्य है कि सरकार मॉनटरिंग कमेटी से बातचीत कर व्यापारियों को राहत देने के बारे में विचार कर रही है?	<b>शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)</b> ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग की जानकारी में नहीं है।

  
**R. S. Parmar**  
 Dy. Secy. (Urban Development)  
 Govt. of NCT of Delhi  
 Delhi Secretariat